(d) The investment of Rs. 383.50 crores is for ongoing and new projects during the current year only.

(e) The production during the current year is expected to go up to 113.50 million tonnes. Investment programme for the next year has not yet been formulated.

(f) The demand of coal during 1980-81 is estimated at 119.80 million tonnes against tentative production programme of 113.50 million tonnes which is under revision.

Regulation of Excess Production in Drug Industry

2509. SHRI SURYA NARAIN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government propose to regularies excess production in the drug industry;

(b) if so, the details; and

(c) whether this move is inconsistent with the recommendation of the Hathi Committee report on drug industry?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Yes Sir.

(b) Details in this regard are indicated in paragraphs 27 to 36 of the Statement (laid on the Table of Lok Sabha on 29th March, 1978 by the then Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers) containing Government's decisions on the Report of the (Hathi) Committee on Drugs & Pharmaceutical Industry.

(c) Government's comprehensive decisions on regularisation of excess production are based on, and are, by and large, in accord with the Hathi Committee's recommendations.

डीजल की खपत

2510. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में डीजल की खपत कितनी है ; और

(ख) निकट भविष्य में डीजल और मिट्टी के तेल उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में, हाई स्पीड डीजल की कुल खपत करीब 9.73 मि० मी० टन थी ।

(ख) इस समय असम से मिलने वाले तेल पर काम करने वाली शोधनशालायें पूर्ण रूप से बन्द रहने या रुक-रुक कर काम करने के कारण हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल दोनों की स्वदेशी उपलब्धता में गिरावट आई है । इस कमी को इन दो उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है जोकि पिछले कुछ महीनों में अधिकतम किया गया है ताकि तटीय स्थानों पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। देश के ऊपरी भागों के स्थानों पर इन उत्पादों की उपलब्धता परिवहन क्षमता पर निर्भर है। डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि तभी सम्भव होगी जब 6 मि० मी० टन क्षमता वाली मथुरा शोधनशाला में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा और अगले एक वर्ष के दौरान बोंगई गांव शोधनशाला अपनी 1 मि०मी० टन की पूर्ण क्षमता पहुंच जाऐगी ।

माही नदी पर कडाना बांध का निर्माण करने के लिये गुजरात और राजस्थान के बीच करार

2511. **श्री बोलत राम सारण** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर उच्चस्तरीय टैंक का निर्माण पूरा होने तक राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों तथा गुजरात के जिला खेरा में सिंचाई के लिये पानी का उपयोग करने हेतु 419 फुट की ऊंचाई का माही नदी में कडाना बांध और 931 फुट के स्तर पर बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध का निर्माण करने के लिये गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने इन दो राज्य सरकारों के बीच हुए इस समझौते के बाद ही परियोजना की स्वीकृति दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों में पानी कब तक उपलब्ध होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय): (क) और (ख). गुजरात और राजस्थानी सरकारों के बीच गुजरात में माही नदी पर एफ0 आर0 एल0 419 फुट सहित कडाना बांध और राजस्थान में माही नदी पर एफ0 आर0 एल0 221 फुट सहित बांसवाड़ा बांध (बजाजसागर बांध) के निर्माण के लिए जनवरी, 1966 में एक करार हुआ था । योजना आयोग ने गुजरात की कडाना परियोजना को दिसम्बर, 1966 में और राजस्थान की माही बजाज सागर परियोजना को नवम्बर 1971 में मंजूरी दी थी ।

(ग) जनवरी, 1966 के करार में यह उल्लेख है कि बाद में जब नर्मदा का विकास हो जाएगा और जब माही क्षेत्रों को नर्मदा का जल मिलने लगेगा तब माही का जल राजस्थान में इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा । गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में नर्मदा के जल से माही क्षेत्रों के पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और इसलिए राजस्थान के जालौर और बाड़मेर क्षेत्रों में जल के इस्तेमाल के लिए माही के जल को देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Plan for Drainage and Irrigation in Sundarban Areas

2512. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the West Bengal Government prepared a master plan for drainage and irrigation in Sundarban areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that this project has not yet been cleared by the Central Government; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) & (b). The State Government of West Bengal has prepared the Sundarbans Delta Project Phase I, at an estimated cost of Rs. 47.3 crores (revised cost). The scheme envisages reclamation and development of 50,000 hectares of Sundarban delta by preventing inundation from saline waters, creating sweet water reservoirs in the area and providing a proper drainage system.

(c) & (d). The comments of the Government of India on the scheme were furnished to the State Government after detailed examination. These have not yet been fully attended to by the State Government.

Export of Films to South Africa

2513. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint that most of the Films are exported to South Africa;

(b) whether it is also a fact that this illegal practice is in process for many years; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI RAMDULARI SINHA): (a) Some producers and exporters of Indian films have complained to the Government that prints of their films are pirated to South Africa.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government regards the clandestine exhibition of Indian films in South Africa as exploitation by some parties of India's trade boycott of South Africa.

Meeting of Experts and Suggestions made therein to improve Hydel Projects

2514. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether a meeting of the experts of the Central Electricity